(d) 39 project proposals under the RLEGP were received before the 16th November, 1983 from the State and Union Territory Governments. The project proposals were considered by the Central Committee on NREP/RLEGP in its meeting dated 17.11.1983 and 23 projects were approved.

Subsequently more than 75 project proposals have been received. These are being examined.

(e) The main difference between the RLEGP and NREP are indicated in the Statement.

Statement

The main differences between the RLEGP and the NREP are as follows :—

(1) While the objective of the RLEGP is to improve and expand employment opportunities for rural landless with a view to providing guarantee of employment to atleast one member of every landless labour household upto 100 days in a year, the objective of the NREP is generation of additional gainful employment for the unemployed and under-employed persons.

(2) The expenditure under the RLEGP is fully funded by the Central Government while under the NREP the expenditure is shared between the Central Government and the State Governments on 50 : 50 basis.

(3) Under the RLEGP, the State and UT Governments are required to prepare specific work projects which are to be sent to the Ministry of Rural Development for approval and sanction by the Central Committee. However, under the NREP, the shelf of projects and annual action plan is to be prepared and approved by the DRDA.

(4) While under the RLEGP, allocations are made to the States and UTs on the basis of 75% weightage being given to the number of agricultural workers and marginal farmers and 25% weightage being given to the incidence of poverty, there is no district-wise allocation of funds. In the case of NREP the States are required to make further allocations to the districts on the basis of this criteria.

अशोक नगर, दिल्ली में सड़कों के निर्माण कार्यों का पूरा होना

4328. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक नगर 20, मानक विहार के उन स्थानों सड़कों/गलियों के नाम क्या हैं जिनके लिए मिनी गन्दगी विकास द्वारा 1982-83 वर्ष के लिए अनुमान तैयार किए गए थे;

(ख) इस क्षेत्र में जनवरी, 1982 से अक्तूबर, 1983 के बीच की अवधि के दौरान किए गए कार्यों का स्थानवार ब्यौरा क्या है और क्या इस अवधि के दौरान शुरू किए गए सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिये गये हैं अथवा अधूरे छोड़ दिए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि जबकि पांच महीने बीत गए हैं जब मानक विहार, फतेह नगर, अशोक पार्क और हरिनगर की सड़कों/गलियों में रोड़ी बिछाई गई थी और अब तक कोई कोलतार नहीं डाली गई है; और

(घ) इसके और अन्य देरियों के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त ार्यों के कब पूरा होने की सम्भावना है?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि मानक विहार में सड़कों तथा नालियों के सुधार कार्य के लिए वर्ष 1982-83 के दौरान निम्नलिखित दो आंकलनों को स्वीकृत किया गया था :

(i) ए तथा बी ब्लाकों में सड़कों पर रोड़ी

तथा पूर्व मिश्रण विकृत अनुमानित लागत 48,840 रुपये ।

(ii) ब्लाक ए गली संख्या 9 में खड़ंजे तथा नालियां बनाना अनुमानित लागत 13,350 रुपये ।

(ख) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित कार्य के मामले में सड़कों पर रोड़ी बिछाने का कार्य पूरा हो गया है । उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित कार्य को ठेकेदार को दे दिया गया है ।

(ग) और (घ) मानक विहार, फतेह नगर, अशोक पार्क और हरि नगर कालोनियों में सड़कों पर रोड़ी बिछाने के विभिन्न कार्य कर दिये गये हैं । इन कालोनियों में पूर्व मिश्रण कार्य भी आरम्भ कर दिये गये हैं ।

स्वयंसेवी संगठनों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान

4329. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान सहकारी पाइलट परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और स्वयंसेवी संगठनों को मजबूत बनाने की दृष्टि से स्वयंसेवी संगठनों को राज्यों और संघ क्षेत्रों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कार्य के लिए इनमें से प्रत्येक संगठन को दी गई धनराशि का उल्लेख करते हुए ऐसे संगठनों के लिए प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र को कितनी धनराशि दी गई है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की छठी योजना स्कीम के अन्तर्गत अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित दो घटकों के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है :—

(1) युवक मण्डलों/महिला मण्डलों को सुदृढ़ बनाने हेतु संघ शासित क्षेत्रों को सहायता.

(2) जन सहयोग की प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता ।

(ख) महिला मण्डलों/युवक मण्डलों को सुदृढ़ बनाने के लिए संघ शासित क्षेत्रों को दी गयी धनराशि का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है । केन्द्र द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता

विवरण-I

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला मण्डलों/युवक मण्डलों को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा संघ शासित क्षेत्रों को बंटित निधियां

क्रम सं०	संघ शासित क्षेत्र का नाम	अभी तक बंटित धनराशि (लाख रुपये में)
1.	चण्डीगढ़	0.09
2.	दिल्ली	0.14
3.	गोआ	0.22
4.	लक्षद्वीप	0.12
5.	मिजोरम	0.24
6.	पांडिचेरी	0.20
	कुल	1.01 लाख